+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

YOJANA MAGAZINE ANALYSIS

(योजना पत्रिका विश्लेषण)

(केंद्रीय बजट - 2025-26)

(March 2025)

(Part IV)

TOPICS TO BE COVERED

- आर्थिक विकास के लिए उत्पादन और उपभोग में संतुलन
- कृषि: विकास का मूल आधार
- NEP 2020 के बढ़ते कदम: सुगम्यता और समावेशिता को बढ़ावा

आर्थिक विकास के लिए उत्पादन और उपभोग में संतुलन:

बजट में प्रत्यक्ष कर सुधार की पहल:

- कराधान में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर शामिल रहते हैं। प्रत्यक्ष करों को प्रोग्रेसिव (आरोही) कर कहा जाता है जिसमे करयोग्य आय के अनुपात मे कर भी बढ़ता है जबकि अप्रत्यक्ष करों को रिग्रेसिव (प्रतिगामी) कर कहा जाता है जैसा कि वस्तु और सेवा कर सभी वर्गों के लिए समान रहता है।
- भारत में अप्रत्यक्ष करों में सबसे बड़ा सुधार 2016 में किया गया था जब वस्तु एवं सेवा कर (GST) को 1 जुलाई, 2017 से लागू किया गया था। अब 2025 में प्रत्यक्ष कर व्यवस्था में 1961 के बाद इसी तरह के बड़े बदलावों की उम्मीद है क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री ने नई आयकर प्रणाली में व्यापक बदलाव लाने की घोषणा की है और 60 वर्ष से भी ज्यादा पुराने कानून की जगह नया आयकर विधेयक लाने का प्रस्ताव रखा है।

प्रत्यक्ष कर सुधारों का मध्यवर्ग पर सकारात्मक प्रभाव:

- मध्यम वर्ग के आयकर दाताओं की संख्या कम होने के बावजूद, वे कर-प्राप्ति और आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- वित्त वर्ष 2023-24 में कुल कर राजस्व 34.5 लाख करोड़ रुपये था, जिसमें प्रत्यक्ष करों (निगम कर व आयकर) का योगदान 19.50 लाख करोड़ रुपये (56%) रहा। आयकर से प्राप्त राजस्व 10.45 लाख करोड़ रुपये था, जो प्रत्यक्ष करों का लगभग 53% है।
- उल्लेखनीय है कि नई कर व्यवस्था के तहत, 1 करोड़ करदाता आयकर के दायरे से बाहर हो जाएंगे और पहले के 5 करोड़ अन्य करमुक्त करदाताओं में शामिल हो जाएंगे।

नई आयकर नीति और उपभोग वृद्धि: अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव

- केंद्र सरकार के कर छूट और स्लैब संशोधनों से 1 लाख करोड़ रुपये करदाताओं के हाथ में आएंगे, जिनमें अधिकांश मध्यम वर्ग से होंगे। इस राशि को चार प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है-खर्च करके, विभिन्न जमाओं के रूप में बचत करके, निवेश करके या पुराने ऋणों का चरणबद्ध भुगतान करके।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- खपत पर मुख्य ध्यान केंद्रित होने से अनुमान है कि इससे 3.3 लाख करोड़ रुपये की आर्थिक गतिविधि उत्पन्न होगी। भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति (MPC) 0.6-0.7 होने पर 65,000-70,000 करोड़ रुपये बाजार में आएंगे। कीन्स के राजकोषीय गुणक सिद्धांत के अनुसार, यह राशि 3-3.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है, जिससे उत्पादन और निवेश में तेजी आएगी और अर्थव्यवस्था को व्यापक लाभ होगा।
- वहीं भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा 5 वर्षों बाद रेपो दर में कटौती से वित्तीय चक्र को और गति मिलेगी।
- इस वित्तीय चक्र की मूल अवधारणा यह है कि एक सकारात्मक बदलाव दूसरे सार्थक बदलाव को जन्म देता है। उदाहरण के तौर पर, जब लोगों के पास अधिक धन होगा, तो उनकी मांग बढ़ेगी। बढ़ी हुई मांग के कारण कंपनियां उत्पादन बढ़ाएंगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रोजगार बढ़ने से लोगों की आय में वृद्धि होगी, जिससे फिर से मांग में इजाफा होगा। इस तरह, अर्थव्यवस्था में विकास का एक सतत चक्र चलता रहेगा।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

अतिरिक्त उपभोग से आर्थिक वृद्धि और कर राजस्व में बढ़ोतरी:

- उल्लेखनीय है कि अतिरिक्त आय से उपभोक्ता वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, पोषक खाद्य पदार्थों और सेवाओं पर अधिक खर्च करेंगे, जिससे निर्माण और सेवा क्षेत्र को लाभ मिलेगा। क्वांटिको की रिपोर्ट के अनुसार, निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE) में वृद्धि से सकल घरेलू उत्पाद (GDP) पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, खासकर परिवहन, वस्त्र, आभूषण और अन्य सेवाओं में उपभोग बढ़ेगा, जिससे राजकोषीय वृद्धि को मजबूती मिलेगी।
- इसके अलावा, 3.3 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च पर 12% GST के तहत सरकार को 40,000 करोड़ रुपये का अप्रत्यक्ष कर राजस्व मिलेगा, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपये केंद्र और 20,000 करोड़ रुपये राज्यों को मिलेंगे। हस्तांतरण फार्मूले के अनुसार, केंद्र से 8,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त राज्यों को हस्तांतरित किए जाएंगे, जिससे राज्यों को कुल 28,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा।
- इस अप्रत्यक्ष कर वृद्धि से सरकारी वित्त मजबूत होगा और आर्थिक गतिविधियों तथा सार्वजनिक व्यय का सतत चक्र जारी रहेगा।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

भारत सरकार द्वारा नया आयकर कानून लाने की योजना:

- वित्त मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में कराधान सुधार महत्वपूर्ण हैं। नए आयकर कानून में न्याय और सरलता की भावना होगी।
- नया आयकर विधेयक मौजूदा कानून की तुलना में आकार में आधा, लेकिन अधिक स्पष्ट और सरल होगा, जिससे करदाताओं और कर प्रशासकों के लिए इसे समझना आसान होगा। इससे कर प्रणाली में निश्चितता आएगी और मुकदमेबाजी में कमी होगी।
- उल्लेखनीय है कि 1961 के पुराने कर कानून में लगातार संशोधनों के कारण यह जटिल हो गया है, और वैश्विक मानकों को ध्यान में रखते हुए अब एक समकालीन कर प्रणाली की आवश्यकता है।

नए आयकर विधेयक की पृष्ठभूमि और आवश्यकता:

- 2010 और 2013 में प्रत्यक्ष कर संहिता लाने का प्रयास हुआ था, जिसका मूल उद्देश्य सरलीकरण था। हालांकि, इसके कई प्रावधानों को आयकर कानून, 1961 में संशोधन के माध्यम से ही लागू कर दिया गया।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद, 2017 में प्रत्यक्ष कर सुधार कार्यदल बनाया गया, जिसने 2019 में सुझाव दिए कि कर प्रणाली में स्थिरता लाने के लिए वार्षिक बदलावों की बजाय आयकर दरों को तर्कसंगत बनाया जाए। इन सुझावों को नए आयकर विधेयक का आधार बनाया गया और 2024 में इस पर और विचार-विमर्श हुआ।

अप्रत्यक्ष करों में सुधार: सीमा शुल्क

- जुलाई, 2024 के बजट में घोषित कस्टम (सीमा शुल्क) दर ढांचे की व्यापक समीक्षा के तहत होने वाले उपायों की चर्चा किए बिना कर-प्रणाली में सुधारों की बात अधूरी ही रह जाएगी। इसमें कस्टम ड्यूटी संरचना की व्यापक समीक्षा के तहत सात शुल्क दरों को समाप्त करने का प्रस्ताव लाया गया है। इससे अब कुल आठ शुल्क दरें (शून्य दर सहित) शेष रह जाएंगी।
- प्रभावी शुल्क प्रणाली बनाए रखने के लिए, कुछ मदों को छोड़कर, उपयुक्त शुल्क लागू करने का प्रस्ताव है, जिससे केवल एक ही शुल्क या सरचार्ज रहेगा। साथ ही, 82 शुल्क मदों को समाज कल्याण अधिभार से मुक्त किया गया है, जिससे पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।

- इसके अलावा, विदेश व्यापार के तहत अस्थायी आकलन को अंतिम रूप से तय करने की समय-सीमा 2 वर्ष तय की गई है, जिसे एक वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। पहले, कोई निश्चित समय-सीमा नहीं थी, जिससे व्यापार में अनिश्चितता और लागत बढ़ रही थी।

बजट में व्यापार सुगमता सुधार प्रस्ताव:

- बजट में व्यापार सुगमता के लिए दो प्रमुख प्रस्ताव रखे गए हैं:
  - ➢ आयातकों और निर्यातकों को वस्तुओं की अनुमति मिलने के बाद स्वेच्छा से असल तथ्य घोषित करने और पेनल्टी के बजाय ब्याज तय करने की सुविधा मिलेगी, जिससे नियमों के पालन को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, यह व्यवस्था उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां लेखा परीक्षा (ऑडिट) या जांच पहले से जारी है।
  - ➢ आयातित आदानों के उपयोग की समय-सीमा 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी जाएगी, जिससे लागत और आपूर्ति अनिश्चितता को कम कर लचीलापन मिलेगा। साथ ही, मासिक विवरणी के बजाय त्रैमासिक विवरणी भरने की सुविधा दी जाएगी।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

बजट 2025-26 में कर सुधारों का उद्देश्य:

- नई आयकर व्यवस्था का पुनर्गठन उपभोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, जबकि सीमा शुल्क सुधार घरेलू निर्माताओं को सशक्त बनाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने में मदद करेंगे।
- आखिरकार, आर्थिक विकास को केवल सकल घरेलू उत्पाद या GDP (जो माँग का प्रतिनिधित्व करता है) के संदर्भ में ही नहीं बल्कि सकल मूल्य वर्धित या GVA (जो आपूर्ति का प्रतिनिधित्व करता है) के संदर्भ में भी मापा जाता है और केंद्रीय बजट 2025-26 में कर सुधारों का उद्देश्य दोनों को संबोधित करना है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

कृषि: विकास का मूल आधार

परिचय:

- कृषि की वृद्धि और उत्पादकता को बढ़ावा देना केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित विकास उपायों में से एक है। कृषि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSME), निवेश और निर्यात के साथ चार शक्तिशाली इंजनों में से एक है।

- केंद्रीय बजट में कृषि में उत्पादकता और लचीलापन बढ़ाने के लिए प्रस्तावित विशिष्ट उपाय इस प्रकार हैं:

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना:

- आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित होकर, भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' शुरू करेगी।
- मौजूदा योजनाओं और विशिष्ट उपायों के संयोजन से, यह कार्यक्रम 100 जिलों को कवर करेगा, जिनकी उत्पादकता कम है, फसल की घनता मध्यम है और जो औसत से नीचे के क्रेडिट मापदंडों वाले हैं।

- यह योजना कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण, स्थायी कृषि प्रथाओं, भंडारण क्षमता, सिंचाई सुविधाओं और कृषि क्रेडिट की उपलब्धता में सुधार पर केंद्रित होगी। इससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की संभावना है।

'ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन' कार्यक्रम:

- राज्यों के साथ साझेदारी में एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय 'ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन' कार्यक्रम लॉन्च किया जाएगा।
- यह कृषि में कम रोजगार को कुशलता, निवेश, प्रौद्योगिकी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करके हल करेगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर उत्पन्न करना है ताकि प्रवासन एक विकल्प बने, लेकिन आवश्यकता न हो।
- यह कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों, ग्रामीण युवाओं, छोटे और सीमांत किसानों और भूमिहीन परिवारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

'दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन':

- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने दालों में आत्मनिर्भरता के लिए ठोस प्रयास किए, जिससे किसानों ने 50% अधिक क्षेत्र में दालों की खेती की और सरकार ने खरीद व लाभकारी मूल्य की व्यवस्था की। इससे उत्पादन और खपत में वृद्धि हुई।

- अब, सरकार 6 साल का 'दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन' शुरू करेगी, जिसमें तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य जलवायु-प्रतिरोधी बीजों का विकास, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना, उत्पादकता सुधारना, भंडारण सुविधाएं बढ़ाना और किसानों को लाभकारी मूल्य की गारंटी देना है।
- केंद्रीय एजेंसियां राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (NCCF) अगले 4 वर्षों में किसानों से इन तीन दालों की खरीद सुनिश्चित करेंगे।

सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम:

- यह उत्साहजनक है कि लोग अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं। यह एक स्वस्थ समाज के बनने का संकेत है। बढ़ती आय स्तर के साथ, सब्जियों, फलों और श्री अन्न की खपत में महत्वपूर्ण वृद्धि हो रही है।
- ऐसे में सब्जियों और फलों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम को राज्यों के साथ साझेदारी में उत्पादन, कुशल आपूर्ति, प्रसंस्करण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया जाएगा।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के बढ़ते कदम: सुगम्यता और समावेशिता को बढ़ावा

परिचय:

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 बच्चों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी शिक्षा और जीवन कौशल पर जोर देती है। 'निपुण भारत मिशन' नवाचार, शिक्षक प्रशिक्षण और ग्रामीण शिक्षा को मजबूत करके इस लक्ष्य को आगे बढ़ाता है। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2024 में सरकारी स्कूलों की प्रगति और उच्चतम दाखिला दर का उल्लेख किया गया है।

- एनईपी और निपुण भारत मिशन भारत की शिक्षा प्रणाली की कमियों को दूर कर विकसित भारत@2047 के लिए मानव पूंजी प्रतिस्पर्धात्मकता को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

NEP 2020: समग्र शिक्षा और कौशल विकास की दिशा में कदम

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 बच्चों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास के लिए मजबूत आधारभूत शिक्षा पर जोर देती है। यह पारंपरिक रटने की प्रवृत्ति से हटकर महत्वपूर्ण जीवन कौशल विकसित करने पर केंद्रित है।
- इस नीति का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और बच्चों की भावी सफलता के लिए प्रेरणादायी परिवेश प्रदान करना है, जिससे भारत की ऐतिहासिक कमियों को दूर किया जा सके।
- इसकी सफलता को बेहतर दाखिला दर, अध्ययन के परिणामों और कुशल कार्यबल के विकास के आधार पर मापा जा सकता है। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) भी NEP के प्रभाव और ग्रामीण भारत में शिक्षा सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

NEP 2020 को लेकर ASER 2024 का निष्कर्ष:

- ASER 2024 यह रेखांकित करता है कि प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में छात्र कोविड महामारी के व्यवधान से उबरने के अलावा आधारभूत कौशल में अपने महामारी-पूर्व के साथियों से भी आगे निकल गए हैं।

- सरकारी स्कूलों ने निजी स्कूलों की तुलना में आधारभूत कौशल में तेज प्रगति का प्रदर्शन किया है।
- पिछले 20 वर्षों में 6-14 आयु वर्ग के दाखिल हुए बच्चे 2024 में 98.1% पर अपने उच्चतम स्तर पर हैं।
- 2024 में कक्षा एक में अल्पवय के बच्चों की संख्या NEP आचार के अनुरूप 16.7% पर अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है।

'निपुण (NIPUN) भारत मिशन' का महत्वपूर्ण योगदान:

- उल्लेखनीय है कि इस परिवर्तन को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान 'निपुण भारत मिशन' का रहा है। इसमें शामिल हैं:
- **स्पष्ट लक्ष्य:** विशिष्ट आधारभूत कौशल संबंधी उपलब्धियां हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **अभिनव शिक्षा शास्त्र:** शिक्षा को आकर्षक बनाने के लिए खिलौना-आधारित और अनुभवजन्य अध्ययन को प्रोत्साहित करता है।
- **ग्रामीण प्रभावशीलता:** अध्ययन के अंतर को पाटता है जहां पारंपरिक तरीके कम पड़ते हैं।

- **शिक्षक प्रशिक्षण:** शिक्षकों को संदर्भ-विशिष्ट, प्रभावी शिक्षण युक्तियों से लैस करने के लिए गहन कार्यक्रम प्रदान करता है।

मुख्य रुझान:

मजबूत जड़ें: प्री-प्राइमरी दाखिले में लगातार वृद्धि

- प्रीस्कूल स्तर पर 3-5 आयु वर्ग के लिए कवरेज में काफी सुधार हुआ है जो 70% से अधिक है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा का कोई न कोई प्रकार सभी के लिए सुलभ है जो एक उल्लेखनीय उत्साहजनक प्रवृत्ति है।
- **कोविड महामारी के बाद दाखिले की दर में स्थिरता आ गई** है जो 3-5 आयु वर्ग में 2018-24 से स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या में गिरावट से प्रकट होता है।

आंगनवाड़ी की अगुवाई: प्रारंभिक शिक्षा का आधार

- यह प्रवृत्ति अद्भुत है क्योंकि आंगनवाड़ी माता-पिता के लिए अधिक प्रत्यक्ष संबंध सुनिश्चित करती है। यह पोषण, टीकाकरण और स्वस्थ बाल्यावस्था तक बेहतर पहुंच की गारंटी देता है।
- ऐसे **राज्य जहां आंगनवाड़ी दाखिला दर बहुत अधिक है प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास को मजबूत करने के लिए बेहतर स्थिति में** हैं।

स्मार्ट और सुरक्षितः किशोर डिजिटल साक्षरता को अपना रहे हैं

- उपरोक्त घटक को मापने का पहला प्रयास दिखाता है कि **90% से अधिक ग्रामीण किशोरों के पास स्मार्टफोन की सुविधा है।**
- वे शिक्षा से संबंधित ऑनलाइन जानकारी खोजने जैसे कार्यों को करने में सहज हैं और सुरक्षा फीचरों के बारे में जानते हैं।

मजबूत स्कूलः बुनियादी ढांचे में सुधार की दिशा में काम चल रहा है

- कोविड महामारी के मद्देनजर स्कूलों में बेहतर स्वच्छता और सफाई सुविधाएं उपलब्ध हैं।
- बेहतर बुनियादी ढांचे और कक्षा के हालातों ने उपस्थिति में सुधार किया है और शिक्षकों और छात्रों के बीच बेहतर संबंधों को बढ़ावा दिया है।
- परिणामस्वरूप अध्ययन परिणामों में सुधार हुआ है।

निष्कर्षः

- इन परिणामों ने भारत को प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने में सक्षम बनाया है। अगले पांच वर्षों में वंचित बच्चों को प्रदान की गई सहायता अगले

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

पच्चीस वर्षों के लिए राष्ट्र की दिशा तय करेगी। कोविड महामारी के बाद स्कूलों के फिर से खुलने से राज्यों में उत्साहपूर्ण प्रयास देखने को मिले जिससे पहुंच, समावेशिता और बुनियादी अध्ययन के परिणाम बढ़े।

- यह दर्शाता है कि निपुण भारत मिशन के साथ एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में NEP केवल एक शिक्षा सुधार ही नहीं है बल्कि अध्ययन की कमियों को दूर करने, विकसित भारत@2047 के लिए भारत की मानव पूंजी प्रतिस्पर्धात्मकता को सुरक्षित करने के लिए युक्तिपूर्ण निवेश हैं।